



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28—अगस्त 3, 2012 (श्रावण 6, 1934)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28—AUGUST 3, 2012 (SRAVANA 6, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	635	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	731	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1073	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1349
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 5233
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 641
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	635	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	731	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1073	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1349
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5233
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	641
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 जुलाई 2012

संकल्प

सं. के-12012/5/4/2011-यो. एवं अनु./एआईएचबी--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के समसंख्यक संकल्प के माध्यम से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में निम्नलिखितानुसार नये गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के संकल्प के अनुसार गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी पदाधिकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत रहेंगे।

1. श्री मारमगंती राजेंद्र रेड्डी
6-3-609/122 अलामेलू रेजिडेंसी
फ्लेट नं. 501, आनंद नगर कॉलोनी
खैराताबाद, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश
2. श्रीमती गीता जयनधर
पार्षद, गौरीबिदनपुर,
मेरु महावीर रोड गौरीबिदनपुर,
जिला चेक्काबालापुर, कर्नाटक
3. श्री सी. आर. नसीर अहमद
मकान नं. 193, नई मस्जिद रोड
बासवराज पेठ देवनगिरि,
कर्नाटक-577001
4. श्री सईद फारुख अली
52, बी. प्रिंस कॉलोनी
ईदगाह हिल्स, भोपाल
मध्य प्रदेश
5. श्रीमती वसुधा देशमुख
पूर्व राज्य मंत्री, अध्यक्ष महादा
अमरावती, मधुबन कॉलोनी कैप,
अमरावती महाराष्ट्र
6. श्री बिरेन्द्र नाथ पट्टनायक
सीसीसी-26, सिविल टाउनशिप
जिला सुन्दरगढ़
राउरकेला-769004 (ओडिशा)

7. श्रीमती सुत्रा घोष
63, सार्दन एवेन्यु, चौथी मंजिल
कोलकाता-700029
8. श्री बलदेव पंवार
ए-25, हरित विहार, बुराड़ी
दिल्ली-110084
9. श्री तुलसीदास मुखर्जी
11/44, पांडित्य रोड
कोलकाता-700029
10. श्री महेंद्र तनेजा
एन-8, हकीकत नगर,
सहारनपुर-उ. प्र.-247001
11. श्री दीपक कुमार दुबे
एलआईजी-18, पद्मनाभपुर, दुर्ग
छत्तीसगढ़-491004
12. सुश्री किरण बाला जैन
मकान नं. 80, सरकुलर रोड
मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी
(हरियाणा)
13. श्री राज कुमार राजू
प्रतापनगर, रायवाला
सहारनपुर-उ. प्र.-247001

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में बोर्ड की मौजूदा क्षमता 75 सदस्य होगी जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव को शामिल करते हुए 27 सरकारी सदस्य और 45 गैर-सरकारी सदस्य हैं।

तथापि, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के संकल्प में अभिलिखित सभी अन्य निबन्धन और शर्तें यथावत और अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. एस. गुप्ता
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

संकल्प

सं. आर-22011/1/2007-ओआर-I--एतद्धीन विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों पर एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन्स संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति का 16 अक्टूबर, 2010 से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया जाता है। समिति का गठन निम्नानुसार होगा :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	संगठन
	सर्वश्री		
		अध्यक्ष	
1.	अरुण बालाकृष्णन	--	--
		सदस्य	
2.	डॉ. जे. पी. गुप्ता	निदेशक	आरजीआईपीटी, रायबरेली
3.	डॉ. ओ. एम. गर्ग	निदेशक	आईआईपी, देहरादून
4.	डॉ. आर. कुमार	प्रोफेसर, अवकाश प्राप्त	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु
5.	प्रो. शान्तनु राय	प्रोफेसर, रसायन इंजीनियरी विभाग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
6.	प्रो. जी. डी. यादव	निदेशक	आईसीटी, मुंबई
7.	जी. डी. गोयल	निदेशक (वाणिज्यिक)	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
		पदेन सदस्य	
8.	एस. के. श्रीवास्तव	महा निदेशक	हाइड्रोकार्बन्स महा निदेशालय
9.	डॉ. आर. के. मल्होत्रा	निदेशक (अनुसंधान और विकास)	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
10.	बी. एन. बंकापुर	निदेशक (रिफाइनरी)	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
11.	आर. के. सिंह	निदेशक (रिफाइनरी)	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई
12.	के. मुरली	निदेशक (रिफाइनरी)	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई
		सदस्य सचिव	
13.	बी. डी. घोष	कार्यपालक निदेशक	सीएचटी, नई दिल्ली

2. स्थायी आमंत्रिती :

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव (रिफाइनरी) और निदेशक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती होंगे।

(ख) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान और विकास प्रमुख भी समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती होंगे। अध्यक्ष समिति की सहायता करने के लिए समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु किसी अन्य व्यक्ति(यों) को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

3. समिति का कार्यकाल :

समिति द्वारा 16 अक्टूबर, 2010 से कार्य करना शुरू करने की आशा है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए अर्थात् 16 अक्टूबर, 2010 से 15 अक्टूबर, 2013 तक होगा। समिति की बैठक आवश्यक होने पर कभी भी किंतु तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य होगी और समित समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

4. वैज्ञानिक सलाहकार समिति के निबंधन और शर्तें :

(क) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

“विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों और ईंधनों और रसायनों के रूप में उपयोग हेतु हाइड्रोकार्बन्स का इष्टतम प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए उपायों के संबंध में सलाह देना”।

(ख) पदेन सदस्यों/सरकारी अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित विभाग/उपक्रमों द्वारा किया जाएगा। समिति पर होने वाला कोई अन्य व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) शैक्षणिक वर्ग से गैर-सरकारी अधिकारियों/सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का भुगतान सीएचटी द्वारा किया जाएगा। उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए उनके कार्यस्थल से बैठक के स्थान तक की यात्रा के लिए हकदारी श्रेणी में वास्तविक हवाई किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(घ) अध्यक्ष, वैज्ञानिक सलाहकार समिति, जो एक गैर-सरकारी सदस्य हैं, के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय को सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ङ) वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक में भाग लेने के लिए स्थानीय यात्रा के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, एसएसी के सदस्य को वाहन उपलब्ध करवाए जाने की स्थिति में स्थानीय यात्रा के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(च) एसएसी की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए एसएसी के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को 4,000/- रुपए (चार हजार रुपए मात्र) का मानदेय देय होगा।

(छ) अध्यक्ष, एसएसी उन वृत्तिकों/तकनीकी विशेषज्ञों को उपयुक्त/नाममात्र के मानदेय का भुगतान किए जाने की सिफारिश कर सकते हैं, जिनसे

•एसएसी को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के तकनीकी गुणावगुणों के संबंध में अपनी राय देने के लिए प्रस्ताव की समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है,

- जिन्हें तेल उद्योग से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी व्याख्यान देने अथवा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

(ज) समिति को अपेक्षित सचिवालयीन सहायता उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एल. एन. गुप्ता
संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

संकल्प

सं. ई-11015/3/2011-हिन्दी--उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11015/1/2008-हिन्दी, दिनांक 14 जुलाई, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति के सदस्य और कार्य इस प्रकार होंगे :--

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अध्यक्ष

लोक सभा के सदस्य

2. श्री प्रेम दास राई सदस्य
3. श्री बसोरी सिंह मसराम सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

4. श्रीमती माया सिंह सदस्य
5. श्री प्रदीप भट्टाचार्या सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

6. श्री दिनेश चन्द्र यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
7. श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

मंत्रालय द्वारा नामित

8. प्रो. महेंद्र कुमार, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय सदस्य
9. श्री आर. गोपीकृष्णन, उप सम्पादक, केरल कौमुदी, पेट्टा, तिरुवनन्तपुरम सदस्य

10. श्री महेंद्र शर्मा, कवि एवं साहित्यकार, पटौदी, गुड़गांव सदस्य
11. डॉ. हरीश अरोड़ा, कवि एवं स्वतंत्र लेखक, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

12. प्रो. डॉ. (सुश्री) रंजिता कुमारी नायक सदस्य
13. श्री पप्पू खान सदस्य
14. श्री ज्योति कुमार सिंह सदस्य

स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

15. श्री बन्दोपंत पाटील, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा सदस्य
16. श्री जय राम यादव, प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली सदस्य

सरकारी सदस्य

17. सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य
18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य
19. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सदस्य
20. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग सदस्य
21. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सदस्य
22. अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग सदस्य
23. आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग सदस्य
24. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव सदस्य
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली सदस्य
26. अध्यक्ष, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली सदस्य
- 26A. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली सदस्य
27. मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली सदस्य
28. मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय, नई दिल्ली सदस्य
29. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली सदस्य
30. अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई सदस्य
31. महा निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता सदस्य
32. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नई दिल्ली सदस्य
33. पंजीयक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली सदस्य

34. संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी),
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

सदस्य-
सचिव

2. समिति के कार्य

इस समिति के कार्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अधीनवर्ती कार्यालयों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा, परन्तु :--

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने-अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के का.ज्ञा. संख्या-II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग,

राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

गिरीश शंकर
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 19 जून 2012

सं. एफ. 9.54/2004-यू.3ए--जबकि "रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय" बैलूर मठ, पश्चिम बंगाल को इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी, 2005 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत, नए सिरे से वर्ग के तहत एक सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था जिसमें कुछ शर्तें थीं जिनमें से एक थी पांच वर्ष बाद समीक्षा करना।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय" बैलूर मठ, पश्चिम बंगाल के कार्यकरण की इस प्रयोजन हेतु गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से समीक्षा की है।

3. और जबकि, इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत "रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय" बैलूर मठ, पश्चिम बंगाल को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की है।

4. अब, अतः केन्द्र सरकार धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस मामले में यूजीसी की सलाह पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय" को सम विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा जारी रखने को एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है जोकि पूर्णतया इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी, 2005 की शर्तों के अनुसार होगा और यह भी शर्तें होंगी कि वे समय-समय पर यूजीसी तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित विनियमों एवं दिशानिर्देशों का पालन करेंगे जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित सम-विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होती हैं और यह कि वे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का भी पालन करेंगे।

आर. पी. सिसोदिया
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 6th July 2012

RESOLUTION

No. K-12012/5/4/2011-P&R/AIHB—The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 8th December, 2011 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct the following as new non official members of All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 8th December, 2011.

1. Shri Maramganti Rajender Reddy,
6-3-609/122 Alamelu, Residency,
Flat No. 501, Anand Nagar Colony,
Khairatabad, Hyderabad,
Andhra Pradesh.
2. Smt. Geetha Jayandhar,
Councilor, Gauribidanpur, Meru,
Mahaveera Road,
Gaouribidanpur, Chckkaballapur Distt.
Karnataka.
3. Shri C. R. Naseer Ahmed,
House No. 193, New Masjid Road,
Basavraj Peth,
Devangiri Karnataka-577001.
4. Shri Syed Farooq Ali,
52, B. Prince Colony,
Idgah Hills, Bhopal,
Madhya Pradesh.
5. Smt. Vasudha Deshmukh,
Ex State Minister, Chairman MHADA,
Amravati, Madhuban Colony,
Camp, Amravati,
Maharashtra.
6. Shri Birendra Nath Pattanaik
CCC-26, Civil Township,
District Sundargarh,
Rourkela-769004 (Odisha).
7. Smt. Suvra Ghosh,
63, Southern Avenue, 4th Floor,
Kolkata-700029.
8. Shri Baldev Panwar,
A-25, Harit Vihar, Burari,
Delhi-110084.
9. Shri Tulsidas Mukherjee
11/44, Panditiya Road,
Kolkata-700029.

10. Shri Mahendra Taneja,
N-8, Hakikat Nagar,
Saharanpur-U.P.-247001.
11. Shri Deepak Kumar Dubey,
LIG-18 Padmanabhpur, Durg,
Chhatisgarh-91004.
12. Ms. Kiran Bala Jain,
H. No. 80, Circular Road,
Model Town, Ambala City,
(Haryana).
13. Shri Raj Kumar Raju,
Pratapnagar, Raiwala,
Saharanpur-U.P.-247001.

The present strength of the Board shall be 75 Members comprising of Chairman, 27 official Members including Member-Secretary and 45 Non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 8th December 2011 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

S. S. GUPTA
Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 13th October 2010

RESOLUTION

No. R-22011/1/2007-OR-1—The Scientific Advisory Committee (SAC) on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is hereby reconstituted for a period of three years with effect from 16th October, 2010 on the terms and conditions specified hereunder. The composition of the Committee will be as under :—

Sl. No.	Name	Designation	Organization
1	2	3	4
		Chairman	
	S/Shri		
1.	Arun Balakrishnan	—	—
		Members	
2.	Dr. J. P. Gupta	Director	RGIPT, Rae Bareli
3.	Dr. M. O. Garg	Director	IIP, Dehradun

1	2	3	4
4.	Dr. R. Kumar	Professor, Emeritus	IISc, Bangluru
5.	Prof. Shantanu Roy	Professor, Chemical Engineering Deptt.	IIT, Delhi
6.	Prof. G. D. Yadav	Director	ICT, Mumbai
7.	G. D. Goyal	Director (Commercial)	EIL, New Delhi
Ex-Officio Members			
8.	S. K. Srivastava	Director General	DGH, New Delhi
9.	Dr. R. K. Malhotra	Director (R&D)	IOCL, New Delhi
10.	B. N. Bankapur	Director (Refineries)	IOCL, New Delhi
11.	R. K. Singh	Director (Refineries)	BPCL, Mumbai
12.	K. Muarli	Director (Refineries)	HPCL, Mumbai
Member-Secretary			
13.	B. D. Ghosh	Executive Director	CHT, New Delhi

2. Permanent Invitees :

- (a) Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary (R) and Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas will be the permanent invitees to the Committee meetings.
- (b) R&D Heads of IOCL, BPCL, HPCL and EIL will also be the permanent invitees to the Committee meetings. The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. Duration of the SAC :

The Committee is expected to start functioning with effect from 16th October, 2010 and its term will be for three years i.e. 16th October, 2010 to 15th October, 2013. The Committee shall meet as often as necessary but at least once in a quarter and will make suitable recommendations to the Ministry of Petroleum & Natural Gas from time to time.

4. Terms & Conditions of the SAC :—

- (a) The terms of reference of the Committee will be as under :—

"to advise on policies relating to Science and Technology and measures to ensure optimum processing of hydrocarbons for use as fuels and chemicals".

(b) Expenditure on TA/DA of Ex-officio members/ Government Officials/representatives of Public Sector Undertakings will be met by the respective concerned Department/Undertaking(s). Any other expenditure on the Committee will be borne by CHT.

(c) The expenditure on TA/DA of non-officials/members form Academia will be met by CHT. They will be reimbursed entitled class airfare at actual for attending the SAC meetings and travelling from their place of working to the place of meeting.

(d) TA/DA of Chairman-SAC, who is a non-official member, will be borne by CHT.

(e) Local transport for attending the SAC meetings will be reimbursed at actuals. However, in case SAC member is provided with transport, no reimbursement for the local transport shall be made.

(f) An honorarium of Rs. 4,000/- (rupees four thousand) only will be payable to the Chairman and non-official members of the SAC by CHT for participating in each SAC meeting.

(g) The Chairman-SAC may recommend payment of suitable/nominal honorarium to professionals/technical experts, who are :

- Requested to review proposal submitted to SAC for giving their opinion on technical merit of the proposals;
- Invited in the Committee's meeting to deliver technical talks or to provide important inputs on issues of relevance to the Oil Industry.

(h) The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Centre for High Technology.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. N. GUPTA
Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 12th July 2012

RESOLUTION

No. E-11015/3/2011-Hindi—In supersession of Resolution No. E-11015/1/2008-Hindi, dated the 14th July, 2008 issued by the Ministry of Consumer

Affairs, Food & Public Distribution the Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. The composition and the functions of the Samiti will be as follows :—

1. Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Independent Charge) Chairman

Members of Lok Sabha

2. Sh. Prem Das Rai Member
3. Sh. Basori Singh Masram Member

Members of Rajya Sabha

4. Smt. Maya Singh Member
5. Sh. Pradeep Bhattacharya Member

Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

6. Sh. Dinesh Chandra Yadav, M.P. (Lok Sabha) Member
7. Sh. Pradeep Tamta, M.P. (Lok Sabha) Member

Non-Official Members (by the Ministry)

8. Prof. Mahendra Kumar, Ex Prof., University of Delhi Member
9. Sh. R. Gopikrishnan, Sub Editor, Keral Kaumadi, Petta, Thrivanthapuram Member
10. Sh. Mahendra Sharma, Poet & Writer, Pataudi, Gurgaon Member
11. Dr. Harish Arora, Poet and Freelancer, Srinivaspuri, New Delhi Member

Nominated by the Department of Official Language

12. Prof. Dr. (Ms.) Ranjita Kumari Nayak Member
13. Sh. Pappu Khan Member
14. Sh. Jyoti Kumar Singh Member

Representative from Voluntary Organizations

15. Sh. Bandopant Patil, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha Member
16. Sh. Jai Ram Yadav, Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi Member

Officials

17. Secretary, Department of Official Language Member
18. Joint Secretary, Department of Official Language Member

19. Secretary, Department of Food & Public Distribution Member
20. Secretary, Department of Consumer Affairs Member
21. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Member
22. Additional Secretary, Department of Consumer Affairs Member
23. Economic Advisor, Department of Consumer Affairs Member
24. All Joint Secretaries of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Member
25. Chairman & Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi Member
26. Chairman, Central Warehousing Corporation, New Delhi Member
- 26A. Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi Member
27. Chief Director, Directorate of Sugar, New Delhi Member
28. Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vanaspati Oils & Fats, New Delhi Member
29. Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi Member
30. Chairman, Forward Market Commission, Mumbai Member
31. Director General, National Test House, Kolkata Member
32. Managing Director, National Consumer Cooperative Federation, New Delhi Member
33. Registrar, National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi Member
34. Joint Secretary (Incharge of Official Language), Department of Food & Public Distribution Member-Secretary

II. Functions of Samiti

The Samiti would render advice to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and all offices under its Administrative Control on matter relating to the progressive use of Hindi for official purpose and on allied issues falling within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language).

III. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution provided that :

- (a) a member who is a Member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as long as he ceases to be a Member of Parliament;

- (b) ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;
- (c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

IV. General

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. Travelling and Other Allowances

The non-official member will be paid travelling and daily allowance, for attending the meeting of the Samiti as contained in the guidelines issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. II.20034/4/86-OL(A-2) dated 22.01.1987 and as per prescribed rate and rule amended by Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government, Union Territory Administration, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and all the Ministries and Departments of Government of India.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GIRISH SHANKAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 19th June 2012

No. F-9-54/2004-U.3A—Whereas "Ramakrishna Mission Vivekananda University" Belur Math, West Bengal, was declared a deemed to be university under de-novo category under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 5th January, 2005 subject to certain conditions that included a review after five years;

2. And whereas, the UGC has reviewed the functioning of the "Ramakrishna Mission Vivekananda University" Belur Math, West Bengal, through an Expert Committee constituted for this purpose;

3. And, whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC has recommended continuation of the status of 'Deemed-to-be-University' to "Ramakrishna Mission Vivekananda University" Belur Math, West Bengal, under Section 3 of the UGC Act, 1956;

4. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of "Ramakrishna Mission Vivekananda University" Belur Math, West Bengal, as a deemed-to-be-university for the purpose of the aforesaid Act, strictly in terms of this Ministry's notification of even number dated the 5th January, 2005 subject to the conditions that they will adhere to the regulations and guidelines prescribed by the UGC and other statutory bodies, from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956 and that they will also abide by directions issued by Government of India from time to time.

R. P. SISODIA
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012